सेवा और धर्म के नाम पर सबोटाज करें, देश के साथ विश्वासघात करें, कोई फादर फेरर का नाम लेता है—यह सब क्या है? इस देश को समुचित ढंग से—चाहे हिन्दू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो—जो इस देश में रहता है, इस देश का नागरिक है। हम ने कांस्टीचुशन में उन को समान अधिकार दिये हैं। अगर एक बम हैदराबाद में गिरेगा, तो न मिर्जा साहब बचेंगे और न शिव नारायण बचेगा, अगर बस्ती में एक बम गिरेगा तो मुसलमान भी मारे जायेंगे और चमार और पंडित भी मारे जायेंगे—इस लिये हमें इस देश को सही ढंग से चलाना चाहिये····

श्री इन्द्रजीत सिंह मल्होत्रा (जम्मू): काश्मीर में बम गिरा तो आपका क्या हुआ?

श्री शिव नारायण: काश्मीर की प्रोटेक्शन का हम ने इन्तजाम कर रखा है। हम कमजोर नहीं हैं। हम काश्मीर के लोगों को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि वह निश्चिन्त हो कर रहें।

MR. DEPUTY-SPEAKER: The hon. Member may resume his speech on the next occasion. Now we have to take up the half-an-hour discussion.

17.30 hrs.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

SUPPLY OF TRACTORS

श्री रणधीर सिंह (रोहतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, देश के किसान के लिए ट्रैक्टर का मसला एक जिन्दगी और मौत का सवाल बना हुआ है। किसान की बड़ी जबर्दस्त लुटाई होती है, उसकी खाल उधेड़ी जाती है। ट्रैक्टर के मामले में लोग साजिश करके किसान को लूटते हैं। हमारी सरकार किसानों की बड़ी हमदर्द है। हमारे फूड मिनिस्टर देश के छटे हुये बेहतरीन लीडरों में से हैं जोकि किसानों से बड़ी हमदर्दी रखते हैं जिनकी रगों में किसान का खून है। हमारे देश की खुशकिस्मती है कि वे हमारे फूड मिनिस्टर हैं। उनके साथ जो टीम है वह भी किसान-वजीर हैं, उनके दिलों में भी किसान के लिए बड़ी तड़प है। लेकिन मुझे अफसोस है कि इनके होते हुये भी किसानों का कोई पुरसां हाल नहीं है।

डिप्टी स्पीकर महोदय, ट्रैक्टर इस देश में अनाज की पैदावार की जान है। अनाज की पैदावार पर सारे देश की खुशहाली निर्भर करती है। देश की खुशहाली पर हमारे देश के जो 55 करोड़ लोग हैं उनका मुस्तकबिल वास्ता है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि किसान ज्यादा से ज्यादा अनाज पैदा करना चाहता है लेकिन कुछ मफाद-परस्त लोग, कुछ वेस्टेड इन्टेरेस्टस ऐसे हो गए हैं जो हुकुमत की नही चलने देते हैं और उनके हाथों किसान भी बेबस हो गए हैं। मेरे पास रिपोर्ट है, कटिंग्ज भी हैं, हुकुमत की तरफ के दिए गए बयानात हैं, पार्लमेंट में किए गए क्वेश्चन्स हैं और उनके जवाबात हैं और गवर्नमेंट आफ इंडिया ने जो टैरिफ कमीशन बिठाई थी उसकी रिपोर्ट भी है? एक-एक बात और की बड़े जोर से छानबीन की गई लेकिन वही ढाक के तीन पात। किसान बेचारा रोता फिरता है, अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए वह कहता है कि हम ज्यादा अनाज पैदा करना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सरमाएदार कहते हैं कि इस देश में ज्यादा ट्रैक्टर चल नहीं सकते हैं। इस देश में 35 फीसदी किसान ऐसे है जिनके पास जोने के लिये बैल भी नहीं हैं और 80 फीसदी किसान ऐसे हैं जिनके पास छोटी होल्डिंग्ज हैं, वे बैल से खेती करना चाहते हैं, ट्रैक्टर लेना नहीं चाहते हैं और देश की जैसी जमीन है उसमें ट्रैक्टर का इस्तेमाल हो ही नहीं सकता है। यह सारी उनकी दलीलें हैं। उन बेइमान लोगों की जो यह दलीलें हैं क्योंकि किसान को मारना चाहते हैं, जो देश को मारना चाहते हैं और हुकुमत पर भी अपना चंगुल रखना चाहते हैं। इस किस्म के लोगों के इरादे हैं—वे पांच ही हैं—जो कि आज सारे देश में ट्रैक्टर के प्रोडक्शन में मानोपोलिस्ट्स बने हुये हैं। मुझे खुशी है कि अब डि-लाइसेंसिंग कर दिया गया है लेकिन क्या होगा इस डी-लाइसेंसिंग से?

[श्री रणधीर सिंह]

वे तो कहते हैं कि बीस हार्स-पावर से कम के ट्रैक्टर जो हैं वह तो चूंकि इस देश की ऐसी जमीन है जिसमें चल ही नही सकते हैं। और अगर चलेंगे भी तो अगर उनकी उम्र पांच साल की होगी तो दो साल में ही खराब हो जायेंगे, बंजर तोड़ नहीं सकेंगे और जितनी पैदावार उस जमीन में होनी चाहिए वह पैदावार भी आज उस ट्रैक्टर से नही हो पायेगी। जितना भी उनका आर्गूमेन्ट है वह यही है कि बीस हार्स-पावर से नीचे का ट्रैक्टर यहां पर नहीं होना चाहिये क्योंकि फिर वे किसानों की अच्छी लूटाई नहीं पर पायेंगे जो कि बीस पच्चीस पच्चीस हार्व-पावर के ट्रैक्टर मे वे कर सकते हैं लेकिन बीस पच्चीस-हार्स-पावर तक के जो ट्रैक्टर हैं उन को 25–30 हजार में कौन खरीदेगा ? वे ट्रैक्टर इतने नाकाम हैं, इतनी क्वालिटी खराब है कि अगर उसको कोई आपरेट भी करे तो वह रोयेगा अपना माथा पकड़ कर और वह उससे चल नहीं सकेगा। अब वह कहते हैं कि हम बनायेंगे तो यही बनायेंगे, 20 से 50 हार्सपावर के ट्रैक्टर ही बनायेंगे आप की तबीयत हो लो न तबियत हो न लो मगर कीमत इतनी ही रहेगी, इस से कम नहीं करेंगे, 25 हजार से। यही बात नहीं, मुजायका इस बात का कि वह क्वालिटी भी गिरती जा रही है। अगर उस की क्वालिटी अच्छी हो, जैसी कि रशन और युगोस्लाविया के ट्रैक्टरों की है तब भी उस को मान लिया जाय। लेकिन उन की क्वालिटी तो गिरती जा रही है। उसकी मशीन खराब है। और दूसरी तरफ उसके दाम भी बढ़ते जा रहे हैं। इन हालात में बेचारा गरीब आदमी क्या करे ? अब मैं आप की मार्फत हुकुमत से शिकायत करना चाहता हूं। हमारे फूड मिनिस्टर साहब की रगों में किसान का खून है। उन को किसान से बड़ी हमदर्दी है। फिर वह बेबस क्यों हैं ? आप ने अखबार और अपने रेकार्ड के पन्ने काले कर डाले अपने स्टेटमेंट से आप तीसरे दिन स्टेटमेंट देते हैं कि जेकोस्लोवाकिया से और रूस से बहुत सस्ते ट्रैक्टर आयेंगे और किसानों को थोड़ी सी कीमत में मिलेंगे। लेकिन आज हालत यह है कि डी० डी०–14 जिस की कीमत 6 हजार रुपये है उस के ऊपर 10 हजार रुपये का ब्लैक मार्केट है, 16 हजार में भी वह नहीं मिलता। सारे देश में लोग घूमते हैं कि किसी तरह से मिल जाय लेकिन नहीं मिलता। इसी तरह से एक जीपर ट्रैक्टर है जिस पर 8 हजार ब्लैक मार्केट है। फर्गुसन ट्रैक्टर पर भी ब्लैक मार्केट है। कोई ट्रैक्टर ऐसा नहीं है जो कि आसानी से मिल जाय। जो प्रोडयुसर हैं या डीलर हैं सब मिले हुये हैं। साजिश किए हुए हैं। जान बूझ कर किल्लत पैदा करते हैं। क्योंकि वह समझते हैं कि जितनी ज्यादा किल्लत पैदा होगी उतनी ज्यादा कीमतें बढ़ेंगी और गरीब की उतनी ही ज्यादा खाल उधेड़ी जा सकेगी। ऐसी हालतमें इस देश में तरक्की कैसे हो सकती है ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : The purpose of this short discussion is that the hon. Minister should elucidate. You state your case briefly within the minutes.

श्री रणधीर सिंह : मैं आपका बड़ा बेहद मशकूर हूं। मैं यहां पर 40 करोड़ लोगों की बात की तर्जुमानी कर रहा हूं। पीजेंट्री के लिए आज इससे ज्यादा परेशानकुन कोई दूसरा मसला नहीं है। मुझे चार पांच मिनट और दे दें।

उपाध्यक्ष महोदय : दो मिनट में खत्म कर दें।

श्री रणधीर सिंह : दस मिनट तो आप मेरे पूरे ही करेंगे। अभी पांच मिनट मेरे और हैं। एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जैसे कावलर आफ कैरो एक झूठा आदमी था जो कि यह कहता था कि हमारा जहाज आ रहा है और इस तरह से सब की अकल मारता था तो मैं आप से पूछूंगा कि

आप का जहाज रूस और चेकोस्लोवाकिया से कब आयेगा छोटे ट्रैक्टर्स का ? या तो आप कह दीजिए कि नहीं मंगायेंगे और अगर मंगा रहे हैं तो कब मंगा रहे हैं ? अगर उस में कोई रुकावट है तो वह क्या है ? कौनसी शक्ति है जो आपके रास्ते में हायल है। मुझे पता है कि रूस वाले ज्यादा से ज्यादा ट्रैक्टर देना चाहते हैं। जेकोस्लोवाकिया वाले यहां पब्लिक अंडरटेकिंग लगाना चाहते हैं। यू०पी० में कारखाना लगाना चाहते हैं तो फिर क्या वजह है कि आप उन को यहां कारखाना नहीं लगाने देते हैं ? आम लोगों का तो यह ख्याल है कि यहां के जो प्रोड्यूसर्स है वह हुकूमत पर दबाव डालते हैं कि अगर आप बाहर वालों को इजाजत देंगे तो हमें मुनाफा नहीं होगा। इसलिए आप इस बात को साफ करें और बतायें कि क्या उन के दबाव को मान कर आप बाहर वालों को यहां कारखाना लगाने की इजाजत देंगे या नहीं देंगे और अगर नहीं देंगे तो आप के पास इस का आलटरनेटिव क्या है ? सन 71-72 तक इस देश में 50 हजार ट्रैक्टर्स की पर ईयर जरूरत होगी बल्कि मैं समझता हूं कि उससे भी जरूरत पूरी नहीं हो सकेगी।

हमारे यहां पावरटिलर्स की और ट्रैक्टर्स की 1 लाख और 50 हजार की क्रमशः डिमांड है। इन की हमारे देश में बहुत अधिक जरूरत है और इसी कारण इतनी जबरदस्त मांग है। जाहिर है कि किसानों की यह मांग देश के हित में है। जहां दूसरे देशों में किसान को हाथ पर रखते हैं सिर पर बैठाते हैं वहां इस देश में आप किसानों की उन की बुनियादी आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं करते हैं। मैं चाहता हूं कि जो ट्रैक्टर्स 6000 रुपये में मिलते हैं उन की कीमत को सरकार सबसिडाइज करे और किसानों को वह 3000 में पड़ें लेकिन हालत यह हो रही है कि 6000 रुपये वाले ट्रैक्टर्स उसे 16000 रुपये में नहीं मिलते। ऐसी हालत के

35LSS/68—12

रहते कौन आदमी कहेगा कि थोड़ी बहुत एक परसेंट भी हुकूमत में किसानों के लिए हमदर्दी है ? मैं इस सिलसिले में यह भी कहना चाहूंगा कि जहां आप प्रोजैक्ट करें वह प्रोजैक्ट बहुत आगे के लिये नहीं अपितु 2-4 साल के लिये करें।

दूसरी बात जो आपने करनी है वह यह कि किसान को ट्रैक्टर खरीदने के लिए कोई आप एक क्रेडिट बौडी कायम करें। यह जो आप ने एग्रो इंडस्ट्रीज वाला महकमा खोल दिया है तो दरअसल यह लोग तो प्राइवेट एजेंसीस से भी ज्यादा खतरनाक है। प्राइवेट एजेंसीज यह जो डिस्ट्रिब्युशन की हैं उन्होंने किसानों को चूसना शुरू कर दिया है। इसलिए क्या सरकार इस के लिये ट्रैक्टर्स-कम-फर्टिलाइजर्स कम-ट्यूबवैल्स की कोई एक ऐसी कारपोरेशन कायम करने के बारे में सोचेगी ताकि किसानों को यह ट्यूबवैल्स, इम्प्रूव्ड सीड्स और ट्रैक्टर्स आदि चीजें जो क्रेडिट पर चाहते हैं वह उन्हें मिल सकें। यह चीजें किसान लोग देश के हित में लेना चाहते हैं और सरकार को यह चीज उन्हें मुहैय्या करने के लिये सभी संभव प्रोत्साहन देना चाहिए।

जिस तरह से देश का डिफेंस जरूरी है वैसे ही बल्कि उस से भी ज्यादा यह अनाज का उत्पादन बढ़ाना देश के हित में जरूरी है। अन्न का मामला अत्यधिक आवश्यक व महत्वपूर्ण है। अब की बार बारिश एक महीना लेट आई जिसके कारण हरियाणे में कोई दाना नहीं होगा और बारिश के एक ही महीना लेट आने से कोई सावनी की फसल नहीं आई। अगर यह चीज नहीं की जायगी और किसानों को यह तमाम सुविधायें समय पर सुलभ नहीं की गई तो अगली फसल भी जोकि कातिक की फसल है वह फसल भी ज्यादा बम्पर नहीं होगी जैसी आप शायद उम्मीद करते हों। इसलिए यह जो देश के अन्नदाता किसान लोग हैं उन के लिये आप क्रेडिट और ट्रैक्टर्स आदि

[श्री रणधीर सिंह]

की सहूलियत सुलभ कीजिये । जिस बात के लिये पार्लियामेंट के फोरम की तरफ से, पार्लियामेंटरी स्टैंडिंग कमेटी ऑन फूड ऐंड एग्रीकलचर की तरफ से और पार्लियामेंट के तमाम मैम्बर्स की तरफ से मांग है और जिसके लिये कि सारे देश को आप ने जय जवान जय किसान का नारा दिया है उस किसान की बुनियादी आवश्यकताओं की सरकार को शीघ्र से शीघ्र पूर्ति करने के लिये ठोस कदम उठाने चाहियें । आज किसान उन अपनी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के अभाव में इधर से उधर परेशान रोते घूमते हैं । जरूरत इस बात की है कि सरकार उनके आंसू पोंछे और उनकी बुनियादी मांग को पूरा करे । ऐसा होने से ही आपका देश में खाद्यान्न के अधिक उत्पादन करने का जो लक्ष्य है वह पूरा हो सकेगा । मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार इन सुझावों पर जरूर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके आवश्यक कार्यवाही करेगी ।

उपाध्यक्ष महोदय, केवल एक वाक्य में आप की इजाजत से और कह देना चाहता हूं कि जो बाहर के हमारे हिन्दुस्तानी हैं वह बतौर गिफ्ट के 38000 ट्रैक्टर्स यहां अपने रिश्तेदारों आदि को देना चाहते हैं लेकिन आप उन को उसकी इजाजत नहीं देते हैं । इसलिये उन्हें यहां आने दीजिये और बाहर के अगर यह 38000 ट्रैक्टर्स जोकि बतौर गिफ्ट के आ जायें तो यहां फ्लड आ जाय और हमारी पैदावार दुगनी हो सकती है । धन्यवाद ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Regarding the half-an-hour discussion, I am going to read out the rule and I shall strictly adhere to the Rules of Procedure. Rule 55(5) reads as follows:

> "There shall be no formal motion before the House nor voting. The member who has given notice may make a short statement and the Minister concerned shall reply shortly. Any Member who has previously intimated to the Speaker may be permitted to ask a question for the purpose of further elucidating any matter of fact."

So, question will be in the nature of elucidation, not speeches.

SHRI INDER J. MALHOTRA (Jammu): What happens to other Members?

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड़) : मैंने प्रश्न पूछने की लिखित रूप से समय से सूचना दी हुई है इसलिये जैसी कि अभी तक यहां प्रक्रिया अपनाई जाती रही है मिनिस्टर के जवाब से पहले प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाय ।

श्री रवि राय (पुरी) : पहले से चली आ रही प्रक्रिया को ही क्यों नहीं जारी रखा जा रहा है ?

MR. DEPUTY-SPEAKER: Those names which have been ballotted will be given a chance. Those Members get an opportunity.

SHRI S. KANDAPPAN (Mettur): The convention has been different.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I am following the rule strictly. The Minister will now reply. For any question by way of elucidation—not speeches—I will permit those Members whose names have come out successful in the ballot. (*Interruption*).

SHRI S. KANDAPPAN: But let him not run away!

SHRI INDER J. MALHOTRA: Does this mean that in the past a wrong practice had been followed in this House?

MR. DEPUTY-SPEAKER: I do not want to say anything. I am only following the practice that has been laid down in the rules.

SHRI INDER J. MALHOTRA: Then for all these years, why this rule was not followed?

MR. DEPUTY-SPEAKER: The Minister.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND CO-OPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE): Mr. Deputy Speaker, I am thankful to the hon. Shri Randhir Singh for raising this discussion on the floor of this House. No doubt the availability of tractors is a very important item from the point of view of development of our agriculture. I think Shri Randhir Singh has expressed his sentiments and those of the hon. House in regard to the shortage of tractors. Though I do not agree with all the statements he made, I share his sentiments that Government should do something so that the availability of tractors is made easy and comfortable in the country.

In this country, our experience during the last few years shows that our farming community is a very enlightened community and if the necessary inputs are made available they can really create wonders on the agricultural front. Fortunately for us, as far as the other inputs are concerned the position is quite satisfactory; take the case of fertilisers: we are in a position to organise a production programme and, at the same time, to have a sizeable import programme so that the requirements of the farmers in regard to fertilisers are being satisfactorily met. In regard to the other inputs, such as machinery which is required for lifting water like pump sets and diesel engines, by the consistent efforts of the Government of India, our country has almost become self-sufficient in the manufacture of diesel engines, electric pumping sets, etc. Not only that. We are even in a position to export some of these items. Even with regard to fertilisers and pesticides, we find ourselves in a comfortable position. But tractor is the one item wherein the progress is not very satisfactory. In fact, as a result of the spectacular progress on the agricultural front, the demand for tractors is growing very fast. Though it is very difficult to make an assessment from year to year, a few years earlier we tried to make an assessment as to what is the annual demand of tractors in this country. And it transpired at that time that the annual demand may be roundabout 25,000 to 30,000 tractors a year. But, now recently, after taking into consideration the demands and the representations received from various quarters, we tried to make a fresh assessment, and it now appears that the demand has almost reached 50,000 a year. These are only rough estimates, but it indicates that the demand is growing very fast and it is likely to grow even faster in the years to come.

How are we to meet this demand? I think in a vast country like ours, the only way to meet this demand is to organise a very sound manufacturing programme. Unfortunately during the last few years, the manufacturing programme did not come upto our expectation. But now the Government has realised the position and that is why the Government has taken a very basic decision that in future no industrialist shall require any licence for putting a tractor factory or a power-tiller factory. This delicensing the tractor industry is a very important step which has been taken in that direction so that the regulations or restrictions on the manufacture do not come in the way of putting up or having a larger manufacturing programme.

That way, though the programme of manufacture is not such as will meet the requirements of our country, I find that gradually our production is going up. For instance, our licensing capacity so far was 30,000 pieces a year, and the installed capacity was 15,000 a year. In 1965-66, the production was only 5,567, but now, in the year 1967-68, the production has reached 11,394, and this year, according to the estimates of the Industries Ministry, the production may reach 20,000 tractors a year. But even then, there is some lag in this, because, as the hon. Member had rightly observed, all these tractors which are manufactured at present in the country have a horse-power range of 20 to 35 or 50.

That means, tractors having lower HP range are not at present being manufactured in the country. Government is seized of this and it trying to see how tractors below 20 HP can be manufactured on a big scale.

[Shri Annasahib Shinde]

Though we have delicensed the industry and taken a number of steps in consultation with the Industry Ministry, production will not come immediately. Naturally we have to import sizeable quantities from outside. As the House is aware, there is shortage of foreign exchange. I do agree with the hon. member that next to defence, agriculture must have the priority. We are trying to see that we import tractors from rupee payment areas. For the last few years, we are trying to import from Czechoslovakia or Russia. There have been some complaints about black-marketing in imported tractors. Government took cognizance of these complaints and some steps have been taken to minimise the malpractices. So far distribution arrangements were with private agencies. At the initiative of my ministry, the decision has been taken that imported tractors would be distributed through public sector agencies *i.e.* the agro-industries corporation. We have urged the State Governments to organise agro-industries corporations which are expected to look to the requirement of machinery and other agricultural inputs. We examine the needs of various areas and on some *ad hoc* basis, we allot quotas out of the imported tractors to the agro-industries corporation. After we started this system, we have not received any complaints of mal-distribution. This is expected to work satisfactorily.

About indigenously produced tractors, Government have taken steps to see that there is some control on price. This matter was referred to the Tariff Commission for examining the cost structure. On their recommendations, the prices of indigenously produced tractors are determined. They are now sold at the prices fixed by Government.

So, to my mind Government is trying to do its level best to see that tractor availability is improved. As I said, there has been some lag in the manufacturing programme. This is receiving the attention of Government and I hope in the near future, Government would take some positive steps to see that the gap between demand and supply is filled up as early as possible.

SHRI RANDHIR SINGH : Why don't you allow people who are residing outside to make gifts of these tractors to their relatives here ?

SHRI ANNASAHIB SHINDE : Government is examining that also.

श्री रवि राय (पुरी) : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जेकोस्लोवाकिया और रूस से जो ट्रैक्टर्स भारत में आते हैं और हमारे यहां जो ट्रैक्टर्स बनते हैं उन के दामों में क्या फर्क है? टैरिफ बोर्ड के मूल्यों के सन्दर्भ में बतलाइये कि हिन्दुस्तान में जो ट्रैक्टर बनते हैं उन की कास्ट आफ प्रोडक्शन क्या होती है और कितने मूल्य में वह किसानों को मिलता है?

दूसरी बात यह कि मुझे पता चला है कि जेकोस्लोवाकिया और रूस से जो ट्रेक्टर्स आते हैं अगर उन के पुर्जे खराब हो जाते हैं तो हिन्दुस्तान में उन के स्पेअर पार्टस नहीं मिलते। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति में जैकोस्लोवाकिया या रूस से मेकनिक्स को बुला कर हिन्दुस्तान के टेकनीशियन्स को ट्रेनिंग देने की कोई व्यवस्था है? मैं यह इस लिये पूछ रहा हूं कि जब कभी मद्रास या पंजाब में या दूसरे प्रदेशों में ट्रेक्टर्स खराब हो जाते हैं तो वह ट्रैक्टर्स चलते ही नहीं क्योंकि हिन्दुस्तानी पुर्जे लगाने से काम नहीं चलता। मैं जानना चाहता हूं कि इसके बारे में आप क्या कर रहे हैं?

SHRI ANNASAHIB SHINDE : In regard to the query made by the hon. Member as to what is the price of imported tractors, the price of DT-14 B which is a Russian tractor is 6,900 and of Zetor Rs. 12,100—the selling price Rs. 13,000. In regard to spare parts, normally the users are allowed to import on the basis of their previous imports etc. But, in addition, we have taken a decision on the basis of which Rs. 40 lakhs of foreign exchange has been made available for importing spares of various tractors; because,

in our country during the last 20 to 30 years various makes of tractors have been imported. At that ime, it was not envisaged that the category of tractors which should be available in the country should be limited so that spares can easily be made available. At that time Renault, Man, Hanomag, Steyr, Lanz, Old Model Massey Harisson and Massey Ferguson and Fordson, all these various types of tractors were imported and we made foreign exchange available for the import of spareparts for these tractors. Then there was a complaint that the shareparts which were imported they were not available to the actual users. So we have taken a policy decision that the Agro-Industries Corporation should be given import licence to import these spares so that the public sector agencies can look after the requirements of the actual users.

श्री भोला नाथ मास्टर (अलवर) : मंत्री महोदय की मिनिस्ट्री से सामुदायिक विकास खण्डों को सब्सिडी, दे कर ट्रैक्टर खरिदवाये गये हैं और उन को जमीन भी पंचायतों से अलाट करवाई है, लेकिन वह सारे ट्रैक्टर खासकर राजस्थान में बेकार पड़े हुए हैं क्योंकि उन को टायर नहीं मिल रहे हैं। इस सम्बन्ध में मैंने टायर कम्पनी को लिखा भी है। उन्होंने कहा है कि अच्छे टायर मिल नहीं रहे हैं। जो नये ट्रैक्टर बनाये जा रहे हैं उन्हीं के लिये नये टायर दिये जाते हैं। इस स्थिति के बारे में मंत्री महोदय क्या सोच रहे हैं। यदि इस के लिये कुछ नहीं किया गया तो जितने भी ट्रेक्टर्स दिये गये हैं वह बेकार पड़े रहेंगे।

दूसरी बात यह है कि दो तीन वर्ष तक ट्रैक्टर्स के आर्डर्स बुक कर लिये जाते हैं। मांच सात वर्ष तक 1,000 रु० फर्म्स के पास पड़ा रहता है और लोगों को उस रुपये का इंटरेस्ट भी नहीं दिया जाता है। इसके बारे में मैं जानना चाहता हूं कि क्या कार्रवाई की जा रही है?

तीसरी बात यह है कि एस्कोर्ट कम्पनी ने हाल में अपने सब एजेंटों को तार दे कर आर्डर दिया कि चूंकि गवर्नमेंट आफ इंडिया ने कीमत बढ़ा दी है और वह उन के लिये ठीक नहीं है इस लिये जो टायर सप्लाई किये जा रहे हैं वह बन्द कर दिये जायें। इस का नतीजा यह हुआ है कि जो एस्कोर्टस के ट्रैक्टर मिल रहे थे वह मिलने बन्द हो गये हैं।

सोशलिस्ट कंट्रीज के बारे में श्री रवी राय ने जो कहा है वह सही है कि वह सस्ते जरूर हैं लेकिन जेकोस्लोवाकिया के ट्रैक्टर्स के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि शायद जो बहुत बड़ा रेवोल्यूशन जेकोस्लोवाकिया में आया उस का कारण यह मालूम होता है कि जो मैसी फरगूसन ट्रैक्टर जेकोस्लोवाकिया से हिन्दुस्तान में भेजा गया है उस की नकल का ट्रैक्टर हिन्दुस्तान में बहुत बड़ी तादाद में बन गया है। वह सस्ते दामों में बना। जो मैसी फरगूसन ट्रैक्टर था उस की नकल का ट्रैक्टर हिन्दुस्तान में तैयार हुआ है और उस की शक्ल वही है। चैकोस्लोवाकिया का उस पर नाम था। शायद इसी वजह से चैकोस्लोवाकिया के ट्रैक्टर आने बन्द हो गए हैं, उसने भेजने बन्द कर दिये हैं। यह मैसी फरगूसन ट्रैक्टर हिन्दुस्तान में सब से ज्यादा पापुलर हुए थे। चैकोस्लोवाकिया एक सोशलिस्ट कंट्री है। शायद रूस ने इसीलिए उसको सजा दी है कि इस प्रकार के ट्रैक्टर उसने हिन्दुस्तान को भेजे जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को सहूलियत मिली। फरगूसन ट्रैक्टर भी शायद इसलिए नहीं आ रहे हैं। इसके बारे में सही स्थिति क्या है ? मैं चाता हूं कि मेरे इन सवालों का मंत्री महोदय जवाब दें।

18 HRS.

SHRI ANNASAHIB SHINDE: The hon. Member has raised a number of

[Shri Annasahib Shinde]

points; I would refer to the most important point in regard to tyres.

The Government of India is seized of the matter; in fact, we consulted the State Government in regard to the availability of tractor tyres and after finding out that there was some shortage we immediately took up the matter with the concerned ministries and a programme has been worked out for importing 5,200 numbers of various makes of tyres. In addition to that the manufacturers of tractors have been allowed to import tyres equivalent to the estimated requirement for three months' production. Again, there is a programme for importing additional 5,000 pieces. The internal manufacturing programme is also being given impetus.

The Massey Ferguson tractor is now being manufactured in our own country.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड़) : शायद माननीय खाद्य तथा कृषि मंत्री महोदय को स्मरण होगा कि मैंने दो तीन किसानों की ट्रैक्टरों के सम्बन्ध में कठिनाइयां उनको पत्र द्वारा भेजी थीं। इस प्रकार के भी समाचार हमारे पास आते हैं कि जिन को नमूने के तौर पर कोई ट्रैक्टर दिखाये जाते हैं लेकिन दिये दूसरे ट्रैक्टर जाते हैं। विदेशी ट्रैक्टरों को आप छोड़ दीजिये, लेकिन जो कम्पनियां भारत में ट्रैक्टर बना रही हैं और जो आर्डर तो बुक नहीं करतीं एडवांस रुपये उधार के नाम पर नहीं लेतीं लेकिन किसी और ढंग से किसानों से पैसा ले लेती हैं क्या वे भी उनके नोटिस में आई हैं? फरीदाबाद की जो कम्पनियां हैं ये तो इस काम में और भी ज्यादा एक्सपर्ट हैं। वे किसानों से पैसा लेने के बाद फिर यह कहती हैं कि तुम को ट्रैक्टर देंगे, सूद भी तुम्हारे रुपये पर देंगे लेकिन जब वे बेचारे पैसा जमा करा देते हैं तो न तो उनके साथ सूद की बात और न ही ट्रैक्टर की बात होती है। दो तीन साल तक वे उनके दरवाजे पर टक्करें मारते हैं लेकिन उन से बात करना भी वे अपना अपमान समझती हैं। क्या कृषि मंत्रालय भारतवर्ष में ट्रैक्टर बनाने वाली जितनी कम्पनियां हैं उन कम्पनियों के सम्बन्ध में यह जानकारी लेंगे कि किसानों का कितना पैसा इन कम्पनियों के पास जमा है और ये कम्पनियां क्या किसानों को उनके पैसे का उसी प्रकार सूद देती हैं जिस प्रकार कि दूसरी जमा पूंजी पर सूद किसानों को मिलता है। जिन किसानों का पैसा जमा होता है क्या उनको उसी प्राथमिकता के आधार पर ट्रैक्टर भी मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, क्या यह मंत्रालय इसका भी पता लगायेगा? ऐसा तो नहीं है कि पैसा तो इनका जमा कर लिया जाता है प्राथमिकता भी इनकी चलती है लेकिन ट्रैक्टर दूसरों को मिल जाते हैं। श्री जगजीवन राम जी को यह सुन कर आश्चर्य होगा कि एक चिट्ठी मैंने श्री फखरुद्दीन अली अहमद को कुछ दिन पूर्व लिखी है कि जिसमें एक किसान ने बीस हजार रुपये एडवांस इसलिए जमा करा दिये और इस वास्ते वह बेचारा भोला भाला किसान उसमें फंस गया कि उस कम्पनी के जो चेयरमैन थे वह हैदराबाद राज्य के भूतपूर्व इंस्पेक्टर जनरल आफ पुलिस थे। उसने सोचा कि जिस कम्पनी के चेयरमैन आई० जी० पुलिस रिटायर्ड हैं वह कम्पनी तो निश्चित रूप से कोई आदर्श कम्पनी होगी। उस बेचारे ने बीस हजार रुपये जो जमा कराये वे फंस गए। ट्रैक्टर भी उसे नहीं मिला, चिट्ठियां भी उसने लिखीं और अब ठोकरें भी वह खाता फिरता है। मैं चाहता हूं कि कृषि मंत्री इन सारी कम्पनियों के सम्बन्ध में चाहे सी० बी० आई० के द्वारा या किसी और उच्चाधिकार प्राप्त समिति के द्वारा जांच करवायें कि कितने करोड़ रुपया किसानों का उनके पास जमा है और उस आधार पर उनको ट्रैक्टर दिये जा रहे हैं या नहीं दिये जा रहे हैं? और अगर नहीं दिये जा रहे हैं तो क्यों नहीं दिये जा

रहे हैं और उस आधार पर उनको इन ट्रैक्टरों को दिलाने की व्यवस्था करें।

मैंने जगजीवन राम जी को एक और पत्र भी लिखा है। उत्तर प्रदेश में किसानों के साथ एक अन्याय हो रहा है जोकि और कहीं भी नहीं हो रहा है ट्रैक्टरों के साथ जो ट्रेलर लगता है जिस से किसान अपनी उपज को मंडी में या बाजार में ले जाता है या घर ले जाता है उस पर भी टैक्स लगता है। और कहीं उस पर टैक्स नहीं लगता है, केवल उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा अभागा प्रान्त है जहां ट्रैक्टर के साथ लगने वाले ट्रेलर पर टैक्स लगता है वाहन कर के तौर से। इसके बारे में मैंने मंत्री महोदय को लिखा भी है। मैं जानना चाहता हूं कि यह अन्याय उत्तर प्रदेश में ही क्यों किसानों के साथ किया जाता है जबकि सम्पूर्ण भारतवर्ष में कहीं इस प्रकार का टैक्स नहीं लगता है।

ये दो सुविधाएं देने के सम्बन्ध में कृषि मंत्रालय क्या कुछ विचार कर रहा है?

SHRI ANNASAHIB SHINDE: In regard to the point raised by the hon. Member I cannot say that there are no malpractices indulged in by certain distributors, but the whole question veers round the point that if the availability is difficult naturally some people try to exploit the situation. So the only remedy to this problem is to see that we increase the availability or indigenous production so that with the increased availability, this situation can be improved.

May I assure the hon. Member, if there are any specific complaints, that we will not hesitate to look into them and see that the culprits are brought to book?

In regard to the point which has been raised by my hon. friend about advances which are taken by these distributors, we have looked into this matter. Formerly, Rs. 2,000 were being taken as advance for a firm order. Now, the present practice is to accept a deposit of Rs. 1,000. Even this is not satisfactorily because of shortage. A large number of people register their names and distributors freely use the amount received by way of deposits. We have now communicated to them that they should accept deposits only if they are in a position to provide tractors within a period 3 months. If this amount which is being reduced to Rs. 1,000, by amending the Tractor Price Control Order, comes to Rs. 100 per tractor, the mal-practices to the extent can be minimised.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Regarding trailers in U.P., what have you got to say?

SHRI ANNASAHEB SHINDE: I shall certainly, look into that.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Shinkre; not present.

The House stands adjourned to meet again on Monday at 11 A.M.

18.07 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, August 12, 1968/*Sravana* 21, 1890 (*Saka*).

L/M35LSS/68—GIPF.